भारत के राजपन The Gazette of India

प्रातारा

EXTRAORDINARY

भाग I --- सम्ब 1

PART I-Section 1

2 8 AUG 1960

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं0 32]

नई बिल्ली, शनिवार, माच 22, 1969/चन 1, 1891

No. 32]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 22, 1969/CHAITRA 1, 1891

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

RESOLUTION

New Delhi, the 22nd March 1969

- No. F. 1(65)-B/68.—The Government of India is pleased to constitute a Team consisting of the following officers to consider certain matters relating to Accounts and Budget Heads arising out of the recommendations of the Administrative Reforms Commission in its Report on "Finance, Accounts and Audit" and "The Machinery of the Government of India and its procedures of work":—
 - Shri A. K. Mukherji, Deputy Comptroller & Auditor General (Convenor).
 - 2. Shri A. R. Shirali, Joint Secretary (Budget).
 - 3. Shri V. M. Bhide, Joint Secretary (Planning Commission) will be coopted as and when matters relating to Plan Heads of Development are considered.
 - An officer of the Administrative Ministry concerned will be co-opted as and when matters relating to that Ministry are considered.

- 2. The terms of reference to the Team will be as follows:
 - (a) (i) To conduct a comprehensive review of the Heads of Accounts and the Heads of Development adopted for Plan purposes on the lines indicated in recommendation No. 2 of the Administrative Reforms Commission's Report on 'Finance, Accounts and Audit' keeping in view the requirements of performance budgeting and the economic classification of the budget; and
 - (ii) to make recommendations for establishing a direct correlation between the Plan Heads of Development and the Heads of Accounts and also between programmes and activities of departments and organisations where performance budgeting is to be introduced and minor heads or subheads of accounts.

While making recommendations on (ii) above the Team will have due regard to recommendation No. 1 of the Report of the Administrative Reforms Commission on 'Finance, Accounts and Audit'.

- (b) (i) To consider recommendation No. 16 of the Administrative Reforms Commission's Report on "Finance, Accounts and Audit" and
- (ii) to recommend measures for streamlining the primary units of appropriation and for making the Demands for Grants and the corresponding central accounts more compact and comprehensive, keeping also in view recommendation No. 13 of the Report of the Administrative Reforms Commission on the "Machinery of the Government of India and its procedures of work" in so far as it relates to the need for making distinct provision in the budget for each wing of a Ministry;
- (c) (i) to review in the context of recommendation No. 17 of the Administrative Reforms Commission's Report on "Finance, Accounts and Audit" the working of the scheme of separation of accounts from audit as introduced in certain Departments in recent years; and
- (ii) to recommend measures in the direction of maintenance of appropriate accounts within the various Departments of Government as an aid to management;
- (d) (i) to study the practical aspects of recommendation No. 18 of the Administrative Reforms Commission's Report on "Finance, Accounts and Audit"; and
- (ii) to make specific recommendations regarding the detailed accounts which should be maintained by the various Departments of Government and the extent to which the details could be eliminated from the accounts maintained in the offices of the Accountants General and other Accounts Offices;
- (e) to review the heads of accounts in the Public Account of the Union and to make recommendations in this regard; and
- (f) to consider any other specific matter that may be referred to the Team by Government.
- 3. The Team shall submit recommendations to Government by 31st March, 1970.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the Convenor and Members of the Team.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information,

विस्त मंत्रालय

(ध्रर्थ विभाग)

संकरप

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1969

संख्या एफ 1 (65)—बी/68.—भारत सरकार प्रशासनिक सुधार प्रायोग की "वित्त, लेखा और लेखा-परीक्षा" ग्रीर "भारत सरकार के तन्त्र और उसकी कार्यप्रणालियाँ" सम्बन्धी रिपोटों में की गयी सिफारिशों से पैदा होने वाले लेखा-शीर्षकों ग्रीर बजट शीर्षकों से सम्बद्ध कुछ मामलों पर विचार करने के लिए सहर्ष एक दल का गठन करती है जिसके सदस्य निम्नलिखित अधिकारी होंगे :

1. श्रीए० के० मुखर्जी,

उप-नियंत्रक महालेखा परीक्षक (संयोजक)

श्री ए० ग्रार० शिराली.

संयुक्त सिचव (बजट)

श्रीवी०एम०भिडे,

संयुक्त सिचिष (योजना भ्रायोग) (जब विकास के भ्रायोजना सम्बन्धी शीर्षकों से संबद्ध भामलों पर विचार किया जाएगा तब इन्हें सहयोजित किया जायगा)

- 4. सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय का एक अधिकारी सहयोजित किया जाएगा जब उस मंत्रालय के सम्बन्ध में मामलों पर विचार किया जायगा।
 - 2. दल के विचारगीय विषय ये होंगे :
 - (क) (i) कार्य-सम्बन्धी बजट तैयार करने भौर बजट का ग्राधिक वर्गीकरण तैयार करने की ग्रावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए "वित्त, लेखा भौर लेखा-परीक्षा" के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार भायोग की रिपोर्ट की दूसरी सिफारिश में निर्दिष्ट तरीकों के ग्रनुसार लेखा शीर्षकों भौर ग्रायोजना के उद्देश्यों के लिए श्रपनाये गये विकास के शीर्षकों की व्यापक समीक्षा करना; श्रीर
 - (ii) विकास के श्रायोजना सम्बन्धी शीर्षकों श्रौर लेखा-शीर्षकों के बीच श्रौर इसके साथ-साथ उन विभागों श्रौर संगठनों के कार्यक्रमों तथा लेखों के लबु-शीर्षकों या उप-शीर्षकों के बीच परस्पर प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सिफारिशें करना जिनके लिए कार्य-सम्बन्धी बजट तैयार करने का काम शुरू किया जाना है।"

उपर्युक्त मद (ii) के सम्बन्ध में सिफारिशें करते समय दल प्रशासिनक सुधार प्राचोग की 'वित्त लेखा, श्रौर लेखा-परीक्षा' सम्बन्धी रिपोर्ट की पहली सिफारिश का भी उचित रूप से ध्यान रखेगा।

(ख) (i) प्रशासनिक सुधार म्रायोग की "वित्त, लेखा म्रौर लेखा-परीक्षा" सम्बन्धी रिपोर्ट की सोलहवीं सिफारिश पर विचार करना ; भौर

- (ii) प्रशासनिक सुधार श्रायोगकी "भारत सरकार के तन्त्र ग्रीर उसकी कार्य-प्रणा-लियाँ सम्बन्धी रिपोर्ट की तेरहवीं सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, जहाँ तक कि इसका सम्बन्ध किसी मंत्रालय की प्रत्येक प्रशाखा के लिए बजट में श्रक्षण से व्यवस्था करने से है, विनियोग की प्रारम्भिक मदों को सरल बनाने श्रीर अनुदानों की मौगों तथा तदनुरूप केन्द्रीय लेखों को श्रीर श्रिक्षक संक्षित तथा व्यापक बनाने के लिए उपायों की सिफारिश करना:
- (ग) (i) प्रशासनिक सुधार श्रायोग की "वित्त, लेखा श्रीर लेखा-परीक्षा" सम्बन्धी रिपोर्ट की सजहवीं सिफारिश को ध्यान में रखते हुए हाल के वर्षों में, कुछ विभागों में लेखा-पालन को लेखा-परीक्षा से धलग करने के लिए शुरू की गयी योजना के काम की प्रगति की समीक्षा करना : श्रीर
 - (ii) सरकार के विभिन्न विभागों में, प्रबन्ध कार्य में सहायता प्रदान करने के उपाय के रूप में, सही तौर पर लेखे रखने की दिशा में उठाये जाने वाले कदमों की सिफारिश करना;
 - (घ) (i) प्रशासनिक सुधार प्रायोग की "वित्त, लेखा ग्रौर लेखापरीक्षा" सम्बन्धी रिपोर्ट की ग्रठारहवीं सिफारिश के व्यावहारिक पहलुग्नों का ग्रध्ययन करना; श्रीर
 - (ii) सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा रखे जाने वाले सविस्तार लखो ग्रौर महालेखाकारों के कार्यालयों तथा लेखा-कार्यालयों में रखे जाने वाले लेखों में से निकासे जाने वाले विवर्णों की सीमा के सम्बन्ध में खास खास सिकारिणों करना; ग्रौर
 - (ङ) केन्द्र के सार्वजनिक लेखे के लेखा-शीर्षकों की समीक्षा करना और इस सम्बन्ध में सिकारिशें करना; और
 - (च) सरकार द्वारा दल को सौंपे जाने वाले किसी ग्रन्थ विशेष मामले पर विचार करना ।
- 3. दल 31 मार्च, 1970 तक सरकार के सामने श्रपनी सिफारिशे पेश कर देगा।

मावेश

अपदेश दिया जाता है कि इत संकल्प को एक प्रति दल के संयोजक और सदस्यों को भज दी जाय।

श्रादेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्वसाधारण की सूचनार्थ भारत के राजपन्न में प्रकाशित किया जाय।

> ए० भ्रार० शिराली, संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।